

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेसपोर्ट सं० 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 आरटीएक्ट में प्रेष किया जिसमें कथन कि याकि कस्बा नोहर के ख. नं. 106 की 8 बीघा 7 बिस्वा, ख० नं० 107 की 5 बीघा 17 बिस्वा, ख० नं० 108/224 की 6 बीघा कुल 20 बीघा 4 बिस्वा यानि 5.109 है 0 मींस वादी की खातेदायी मींस थी। इस मींस पर

दिनांक:- 3. 3. 2022

निर्णय

श्री आनन्द उपाध्याय अधिवक्ता अपीलाएट
श्री मदन मोहन जोशी एवं श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेसपोर्ट सं० 1
श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता रेसपोर्ट सं० 2

प्रकरण संख्या 257/2014 बअनवानी दयालगिरी बनाम अधिशाषी अधिकाारी नगरपालिका
अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 06.04.2018 सहयक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकाारी नोहर

रेसपोर्ट

1. दयालगिरी बेनीा श्री कृष्णानन्दगिरी बेनीा श्री तरकगिरी निवासी नोहर तहसील नोहर हाल मण्डी कलियावाली तहसील मनाट जिला मुक्तसर जसिये मुख्तयार आम अभीलाल पुत्र उदराम पुत्र श्री सुखराम जाति जाट सहराण निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिष्ठी जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान राज्य जसियक तसहीलदार नोहर।

बनाम

अपीलाएट

नगरपालिका नोहर जिला हनुमानगढ जसिय अधिशाषी अधिकाारी नगरपालिका
नोहर जिला हनुमानगढ।

अपील संख्या 2015/00261 (139/2018) 223 आरओएक्ट

पीठासीन अधिकाारी :- करतार सिंह पुनियाँ आर.ए.ए.एस.

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ



राजस्थान अधीन प्राधिकारी
दुर्गा नगर

करने का कोई अधिकार नहीं है। दयालगाँवी इस इलाके में कभी भी नहीं रहा न नहीं की गई कोई नक्शा पेश नहीं किया गया सीधे ही पटवारी को रिपोर्ट पेश व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है। तहसीलदार द्वारा कोई रिपोर्ट न्यायालय में पेश तहत केवल खातेदार काइलकार या सब टिनेन्स ही दावा ला सकते हैं किसी चाहता है। यह मामला स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है टिनेन्सी एकट के रेस्यो का कोई वास्ता नहीं है। रेस्यो नगरपालिका की भूमि को हड़प करना प्राप्त करने का अधिकार नहीं है रेस्योहोट्ट द्वारा चाही गई तबादला में भूमि से बीघा 15 बिस्वा भूमि में नगरपालिका की भूमि थी रेस्यो सं० 1 तबादला में भूमि को आवंटित हुई थी। नगरपालिका ने अपनी आवंटन श्रृंखला भूमि 107/223 की 2 रिफाई में सिवाय एक दर्ज थी जो मौके पर खाली थी और नगरपालिका नोहर भी रेस्यो सं० 1 के कब्जा काइल में नहीं रही। यह भूमि सरकारी भूमि थी जो विद्वान अधिवक्ता अधीलापट्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि कभी 2. उभयपक्ष की बहस सृजनी गई।

पेश की है।

आधिकार रूप से स्वीकार किया, जिससे व्यक्ति होकर अधीलापट्ट ने यह अधीन निषेधाज्ञा जारी करने का अर्जोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद को वादी के नाम बतौर खातेदार दर्ज करने एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध रेफाई उपयोग उपयोग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। वादी ने वादपत्र में उक्त भूमि को प्रतिवादी सं० 1 इस भूमि अवैध तौर से बेचान करने पर आमादा है तथा उसके विपरीत हुई भूमि है जिस वह तबादला में प्राप्त करने का अधिकारी है। लेकिन 69575 है 0 भूमि नगरपालिका क्षेत्र में है आबादी के समीच है जो वादी की भूमि से 0.8090 है 0, या 10 नं० 126/2 की 0.126 है 0 भूमि 2 बीघा 15 बिस्वा यानि 0. की भूमि के विपरीत या 10 नं० 109/247 की 0.3040 है 0, ख 0 नं० 109/248 की एवल में तबादले में 2 बिस्वा 15 बिस्वा भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी 15 बिस्वा भूमि कम हो गई। वादी अपनी स्वयं की भूमि में काटे गये भूखण्ड की ही था। वादी ने बेचान की कोई सहमति नहीं दी थी। जिससे वादी की 2 बीघा कृषि भूमि पर प्लाट के रूप में बेचान कर दी जबकि इसका मूल स्वामित्व वादी बात का फायदा उठाकर ख 0 नं० 107/223 के दक्षिण हिस्सा 2 बीघा 15 बिस्वा गैरमुमकिन आबादी के तौर उपान्तरित करवा लिया गया। नगरपालिका ने उक्त नगरपालिका नोहर में दर्ज होकर गैरमुमकिन आबादी में तब्दील हो गई एवं



राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय
अधीनस्थ न्यायालय

के निर्णय को निरस्त कर दिया जाता है जो रेस्पॉन्ड को अपूर्ण्य एति होगी। रेस्पॉन्ड अपने वैध अधिकारों को प्राप्त करने से वंचित हो जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय को अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (4) 1997 एन 609 व अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (4) 1997 एन 609 व आरआरडी 1973 एन 714 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पॉन्ड सं 2 ने अधीनस्थ न्यायालय की बहस का समर्थन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय स्वीकार करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रकरण में रेस्पॉन्ड सं 1 ने खातेदारी अधिकारों एवं रथाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया कि उसकी भूमि में पैमाइंश किये बिना नगरपालिका ने प्लान काट कर बेवान कर दिया है, एवं भूमि के बदले में क्षतिपूर्ति के रूप में उसके द्वारा ख 0 नं 109/247, 109/48, 126/2 में 2 बीघा 15 बिस्वा प्राप्त करने का निवेदन किया था जिस अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिक रूप से स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय के कथन है कि दयालगिरी का कर्णानंद गिरी का बेला होना संदेहास्पद है। इसलिये दयालगिरी इस भूमि को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त तथ्य की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत एडिशनल डिस्ट्री जल सिस्सा के निर्णय दिनांक 12.06.1997 के द्वारा हाती है, जिसमें दयालगिरी का कर्णानंद गिरी का बेला होना भी संदेहास्पद माना है। रेस्पॉन्ड सं 1 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नगरपालिका के स्वामित्व की भूमि है जिला कलेक्टर महोदय वर्तमानतः द्वारा नगरपालिका को आवंटित की गई है। जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नगरपालिका की रिपोर्ट को आधार मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय निर्णय पारित किया है। जबकि मौका रिपोर्ट तहसीलदार राजस्थान नोहर द्वारा कोई मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है तथा एडिशनल डिस्ट्री जल सिस्सा के निर्णय में दयालगिरी का कर्णानंदगिरी का बेला होना ही संदेहास्पद माना गया है साथ ही दिनेसी एकट के तहत केवल खातेदार काश्तकार या सब दिनेस ही दावा ला सकते हैं रेस्पॉन्ड सं 1 इस भूमि का सब काश्तकार नहीं है और किसी अन्य व्यक्ति को दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पॉन्ड सं 1 प्रथमतः भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय स्वीकार किये जाने योग्य है।



राजस्थान
 शासन
 (करतार सिंह पौन्या आरएस)
 राजस्थान शासन
 राजस्थान शासन



इजलास सुनाया गया।
 निर्णय आज दिनांक 3.3.2022 को से द्वारा लिखाया जाकर से
 दफ्तर हो।

8. उपरोक्त विवेकन एवं विवेक्षण के आधार पर अपील अपीलान्ट रवीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलान्तीन निर्णय दिनांक 06.04.2018 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल